

RIVER KATHA

THE NATIONAL Mission for Clean Ganga, which implements the government's ambitious Namami Gange programme, will hold a one-day Ganga Utsav on Friday. Among activities planned is a mini-food festival, involving local dishes from Ganga riparian states such as Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh and West Bengal. Aside from that, film screening and a storytelling session will also be organised. Union Culture Minister G Kishan Reddy will be chief guest at the event, to be held at Major Dhyani Chand Stadium.

ITC Ltd strengthens its 360-degree Water Stewardship interventions with focus on PPPs

ITC's 360-degree water stewardship programme is in alignment with the Government's key water initiatives including 'Jal Shakti Abhiyan', 'Atal Bhujal Yojana' and 'More Crop Per Drop'

NEW DELHI: ITC Limited, one of India's leading multi-business conglomerates, has forged as many as 50 Public-Private Partnerships (PPPs) with the GoI and other institutions as part of its integrated and holistic initiatives to achieve water security and rural empowerment across India. ITC's 360-degree water stewardship programme is in alignment with the Government's key water initiatives including 'Jal Shakti Abhiyan', 'Atal Bhujal Yojana' and 'More Crop Per Drop'. Driven by the Sustainability 2.0 goals articu-

lated by Chairman, Sanjiv Puri, ITC is scaling up its interventions in replenishing water resources and water usage efficiency. It has also embarked on a programme to achieve water positive status at river basin level with focus on 4 basins across the country. The Ghod river basin has already turned water positive last year.

The Company has also partnered the government in creating large-scale awareness on the need for equitable water management by participating in the ongoing India Water Week 2022.

In recognition of its efforts in ensuring water security for all stakeholders, ITC also received the 1st prize in the 'Best Industry for CSR Activities' category at the third National Water Awards by Ministry of Jal Shakti, GoI in 2021-22.

Over 54 per cent of India is water stressed. Agriculture which forms the lifeline of the Indian economy is vulnerable to the threat of climate change. Recognising the critical need to address this challenge, ITC has taken a three-fold approach to drive water security for its

stakeholders and contribute to achieving the national goal of securing a sustainable water future for India. The three-pronged approach involves 1) a large-scale community based integrated watershed development initiative covering catchment treatment, water harvesting structures development, and groundwater recharge spread over 13 lakh acres in 16 states with over 25,000 water harvesting structures built and another 1.33 lakh acres under biodiversity conservation, 2) a unique demand side

water management programme that focuses on improving water use efficiency of agriculture with the demonstrated achievement of water savings in the range of 20-45 per cent across select crops and a total savings potential of 496 million cubic metres during 2021-22 3) maximizing water efficiency across all its operations. Owing to its 360-degree water stewardship initiatives, ITC has earned the distinction of being the only global company of comparable dimensions to be water positive for over two decades. **MP02**

संगठनों व लोगों की भूमिका तय हो, जल स्रोतों को विकसित करने में मददगार होंगे जन समुदाय जन समुदाय, जल संरक्षण के लिए है सबसे अहम सीढ़ी



घनैंद्र वंदेल • कोटर नोएडा



इंडिया एक्सपोजे सेंटर एंड मार्ट में चल रहे इंडिया वाटर वीक में कुशल जल प्रबंधन में नागरिक समाज की भूमिका सत्र में विचार रखती नूपुर बहादुर व उपस्थित अन्य वक्ता • जागरण

देश ही नहीं दुनिया में बढ़ते जल संकट को दूर करने में सिर्फ सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं होंगे। केंद्र और राज्य सरकारों को नागरिक समाज का योगदान और उसकी भूमिका भी तय करनी होगी। आदि काल से ही जल संरक्षण में समुदाय की अहम भूमिका रही है। सामुदायिक सहभागिता के बिना जल को बचाने के प्रयास पूर्णलक्षित नहीं होंगे। यह सार, ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपोजे सेंटर में आयोजित सातवें इंडिया वाटर वीक में मंचन से निकला। 'कुशल जल प्रबंधन में नागरिक समाज की भूमिका' विषय पर हुए सेमिनार में विशेषज्ञों ने विचार रखते हुए कहा कि देशवासियों

को विरासत में अविरल बहती नदियां, पानी को कोख में समेटे तालाब, झील और पोखर मिले हैं। सभ्यताओं के विकास में प्राकृतिक संसाधनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर कालखंड में मानव सभ्यता ने अपने अनुभव और जरूरत के अनुसार जल संरक्षण व संवर्द्धन के लिए विशेष संरचनाओं का विकास किया। भारत में जल संरक्षण की 40 से अधिक परंपरागत पद्धतियां हैं, जो जल की समृद्ध विरासत के बारे में बताती हैं। विशेषज्ञों ने बढ़ते जल संकट की चुनौती से निपटने के लिए इन विरासत को बचाने और संरक्षित करने की जरूरत पर जोर दिया।

दो दशक पहले जल संरक्षण में सामुदायिक सहभागिता अधिक रही है। जल प्रबंधन में नागरिक समाज की घटती भूमिका पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जल प्रबंधन में जन समुदाय की भूमिका सिमटना भविष्य के लिए खतरनाक संकेत है। जल स्रोत को पुनर्जीवित करने व जल संचयन के लिए जन समुदाय की भूमिका को बढ़ाना ही होगा। योजनाओं के नियंत्रण व क्रियान्वयन में भी उनकी भूमिका तय करनी होगी। तभी जल संकट की चुनौती का सामना किया जा सकता है।

जल विशेषज्ञों में प्रमुख रूप से वाटर एंड के सीईओ वीके माधवन,

पेयजल एवं स्वच्छता विशेषज्ञ डाक्टर असद उमर, धान फाउंडेशन के राजा पांडेयन, टेरी की सीनियर फेलो एंड हेड डाक्टर नूपुर बहादुर, पर्यावरण विधि विशेषज्ञ शहवाहिक सिंहकी शामिल रहे।

ठेकेदार और एजेंसी नहीं, स्थानीय लोग ही अहम भूमिका : विशेषज्ञों ने कहा कि तालाब, नदियों को जिंदा रखने में पहले स्थानीय लोगों के सुझाव और सहयोग लिया जाता था, लेकिन अब उनकी भूमिका को समाप्त कर यह कार्य ठेकेदार, एजेंसियों को सौंप दिया है। इससे गैर सरकारी संगठनों को वह सम्मान नहीं मिल रहा, जो उनके योगदान

के लिए जरूरी है। नीति आयोग के दर्पण पोर्टल में पंजीकरण की अनिवार्यता के कारण भी जन समुदाय के लिए श्रमदान के अवसर घटे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019 में व केंद्र सरकार ने 2012 में जल नीति बनाई। इनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए जन समुदाय की राय लेना भी आवश्यक है। योजनाओं के क्रियान्वयन व निर्माण में भी भूमिका बढ़ाने की जरूरत है।

जल संरक्षण के क्षेत्र में जनसमुदाय के श्रमदान से ही योजनाएं सही ढंग से क्रियान्वित हो सकती हैं। धान फाउंडेशन के राजा पांडेयन ने कहा कि तमिलनाडु में पांच हजार तालाब जन सहयोग से ही बचे हैं। जल विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जल संसाधनों पर सरकारी नियंत्रण को होड़ सी लगी है। सरकार और समुदाय के बीच बातचीत और समन्वय का अभाव है। बुंदेलखंड में जल संचयन पर व्यापक स्तर पर काम करने वाले डाक्टर संजय सिंह ने कहा कि देश में 2050 तक पानी को पुनः उपयोग के योग्य बनाना होगा।

तैयारी: नहर निगरानी से पानी की बर्बादी रुकेगी



ग्रेटर नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। देशभर में इस्तेमाल होने वाले भूमिगत जल में से 87 प्रतिशत पानी सिंचाई के लिए प्रयोग होता है। इसका प्रयोग कम करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने पहल शुरू की है। नहरों के पानी का बेहतर प्रबंधन, फसल की मांग के

अनुरूप पानी छोड़ने, पानी की बर्बादी रोकने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। राजस्थान की तीन नहरों में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ है।

इससे करीब नौ लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल कवर हो जाएगा। अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहे तो इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी चल रही है। ग्रेनो एक्सपो मार्ट में इंडिया वाटर वीक (भारत जल सप्ताह) चल रहा है। इस आयोजन में जल संरक्षण, उसके उपयोग और उपायों पर मंथन हो रहा है। प्रदर्शनी भी यहां लगी है।



ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित भारत जल सप्ताह के तीसरे दिन गुरुवार को स्कूली बच्चों ने जल संरक्षण के लिए जागरूक किया। ● हिन्दुस्तान